प्रेस विज्ञप्ति

iFOREST अनुसंधान से छत्तीसगढ़ में अक्षय ऊर्जा की अपार संभावनाएं उजागर हुईं, नीतिगत कार्रवाई की मांग

रायपुर, 05 अक्टूबर, 2024 : भारत में पर्यावरण अनुसंधान के क्षेत्र में अग्रणी संगठन iFOREST ने आज तीन महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी कीं, जिनमें छत्तीसगढ़ में अक्षय ऊर्जा (RE) के विकास की जबरदस्त संभावनाओं पर प्रकाश डाला गया है। रिपोर्ट में राज्य में हरित ऊर्जा के विकास को गति देने के लिए विस्तार और कार्रवाई योग्य नीतिगत मार्गों के लिए नई अनिवार्यताओं पर भी प्रकाश डाला गया है।

ये रिपोर्टें बेबीलोन कैपिटल, रायपुर में आयोजित 'छत्तीसगढ़ में नवीकरणीय ऊर्जा विकास के अगले चरण को सक्षम बनाना' शीर्षक वाले हितधारक संवाद में जारी की गईं। संवाद में राज्य ऊर्जा विभाग और एजेंसियों, विनियामक आयोग, प्रमुख उद्योगों, डेवलपर्स, थिंक टैंक, शिक्षाविदों और अन्य क्षेत्र के विशेषज्ञों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

छत्तीसगढ़, जो नवीकरणीय ऊर्जा ऑफ-ग्रिड क्षेत्र में अग्रणी है, विशेष रूप से कृषि उपयोग के लिए सौर जल पंपों में, एक महत्वपूर्ण बिंदु पर है। यह अपने ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी का विस्तार करना चाहता है। राज्य ने अपने नवीकरणीय खरीद दायित्वों (आरपीओ) को भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य के साथ जोड़ दिया है, जिसका लक्ष्य 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से 43.3% ऊर्जा खरीद करना है। पिछले महीने गांधीनगर, गुजरात में आयोजित चौथे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन (आरई-इन्वेस्ट) में माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साई ने इस प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

छत्तीसगढ़ में बिजली की मांग लगातार 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है और चालू दशक में उपयोगिता के लिए 6% और कैप्टिव सेगमेंट के लिए 10% की दर से आगे बढ़ने का अनुमान है। इसे देखते हुए, नई आरपीओ प्रतिबद्धताओं से 2031-32 तक लगभग 35 गीगावाट की मांग बढ़ेगी। यह राज्य के भीतर आरई क्षेत्र के विकास के लिए एक मजबूत आधार का प्रतिनिधित्व करता है, जो हरित विकास और रोजगार सृजन को भी बढ़ावा देगा।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग (CSERC) के अध्यक्ष श्री हेमंत वर्मा ने कहा, "छत्तीसगढ़ को व्यापक रूप से वितरित नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी माना जाता है। आयोग ने राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा के विकास को समर्थन देने के लिए राज्य के नियमों को राष्ट्रीय ढांचे के साथ जोड़ दिया है। इससे 1 गीगावाट क्षमता जोड़ने में मदद मिली है। राज्य के लिए दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है।"

छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र के नोडल अधिकारी, आईएफएस श्री अरुण कुमार पांडे ने कहा, "बदली हुई परिस्थितियों के लिए एक बदले हुए दृष्टिकोण की आवश्यकता है। चूंकि जलवायु परिवर्तन की चिंता देश के लिए अधिक से अधिक वास्तविक होती जा रही है, इसलिए राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा विकास के लिए उपयोग की जाने वाली पर्याप्त भूमि और संसाधन हैं।"

एनसीआर कार्यालय: सी - 902, 9 वीं मंजिल, अर्बटेक ट्रेड सेंटर, बी - 35, सेक्टर 132, नोएडा - 201304 उत्तर प्रदेश

पंजीकृत कार्यालय: 15-ए, तृतीय तल, प्रताप नगर, मयूर विहार, दिल्ली - 110091

फ़ोन: +91-120 6137 440 और 011 4309 7307 ईमेल : contact@iforest.global

iFOREST की कार्यक्रम निदेशक सुश्री मांडवी सिंह ने कहा, "छत्तीसगढ़ को जलवायु परिवर्तन को कम करने, स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अपने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विस्तार को प्राथमिकता देनी चाहिए। थर्मल पावर पर राज्य की निर्भरता को देखते हुए, नवीकरणीय ऊर्जा की ओर उचित बदलाव आवश्यक है। इसे हासिल करने के लिए, सरकार को एक दूरदर्शी नीति ढांचे की आवश्यकता है जो निवेश को प्रोत्साहित करे और अपने स्वयं के 'विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़' पहल के साथ संरेखित हो, जिससे राज्य को सतत ऊर्जा विकास में अग्रणी के रूप में स्थापित किया जा सके।"

अभी तक छत्तीसगढ़ का नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ा हुआ है। राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में राज्य की हिस्सेदारी केवल 1.7% है। पिछले पांच वर्षों में, जबकि भारत की क्षमता में 64,232 मेगावाट की वृद्धि हुई है, छत्तीसगढ़ में क्षमता वृद्धि केवल 1,011 मेगावाट रही । हालाँकि, इसमें विस्तार की अपार संभावनाएँ हैं।

अद्यतन आंकड़ों और कार्यप्रणालियों पर आधारित आईफॉरेस्ट के शोध से पता चलता है कि छत्तीसगढ़ की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के पूर्व अनुमानों से काफी अधिक है:

- सौर ऊर्जा की क्षमता 41 गीगावाट से अधिक है, जो एमएनआरई द्वारा अनुमानित क्षमता से दोगुनी है। लगभग 50% क्षमता बोलदा बाजार, सूरजपुर, कोरबा, रायगढ़, जशपुर, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर और रायपुर जिलों में है।

- के 258 बांधों में, फ्लोटिंग सोलर पीवी क्षमता 23.5 गीगावाट (उच्च उपयोग परिदृश्य में) से अधिक होने का अनुमान है। सिकासार बांध सबसे बड़ी व्यक्तिगत क्षमता प्रदान करता है।

- 6 से 7 मीटर/सेकेंड की उच्च पवन गति वाले क्षेत्रों में 150 मीटर हब ऊंचाई पर लगभग 7.4 गीगावाट की सैद्धांतिक क्षमता की पहचान की गई है।

- बायोमास क्षमता 4.2 गीगावाट आंकी गई है , जो एमएनआरई के आकलन से दस गुना ज़्यादा है। राजनांदगांव, जांजगीर-चांपा और रायगढ़ जिले इस क्षमता का लगभग एक तिहाई योगदान देते हैं।

रिपोर्ट में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के विकास के लिए आर्थिक मामले पर प्रकाश डाला गया है। आने वाले वर्षों में अन्य राज्यों से आयात काफी महंगा हो जाएगा क्योंकि अंतर-राज्यीय नवीकरणीय ऊर्जा खरीद पर ट्रांसमिशन लागत पर उपलब्ध छूट 2025 और 2028 के बीच चरणबद्ध तरीके से समाप्त हो जाएगी। iFOREST का अनुमान है कि मौजूदा अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम (ISTS) शुल्क छूट 60 पैसे/यूनिट जितनी अधिक होगी। एक बार जब इन शुल्कों को खरीद लागत में शामिल कर लिया जाता है, तो छत्तीसगढ़ के भीतर स्थित नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों से बिजली खरीदना सस्ता हो जाएगा। इसलिए, iFOREST की रिपोर्ट में पाया गया है कि छत्तीसगढ़ के लिए राज्य के भीतर नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना आर्थिक रूप से विवेकपूर्ण होगा।

हालांकि, एक व्यापक नवीकरणीय ऊर्जा विकास रणनीति अपनाने के लिए राज्य के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए विस्तारित दृष्टिकोण के आधार पर एक नई नीति रूपरेखा स्थापित करना शामिल होगा, उच्च क्षमता वाले नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला गया है कि परियोजना अनुमोदन के लिए एकल खिड़की मंजूरी तंत्र और स्पष्ट एसओपी स्थापित करना महत्वपूर्ण है।

एनसीआर कार्यालय: सी - 902, 9 वीं मंजिल, अर्बटेक ट्रेड सेंटर, बी - 35, सेक्टर 132, नोएडा - 201304 उत्तर प्रदेश

पंजीकृत कार्यालय: 15-ए, तृतीय तल, प्रताप नगर, मयूर विहार, दिल्ली - 110091

फ़ोन: +91-120 6137 440 और 011 4309 7307 ईमेल : contact@iforest.global

iFOREST के बारे में

International Forum for Environment, Sustainability & Technology (iFOREST) गैर-लाभकारी अनुसंधान और नवाचार संगठन है, जिसकी स्थापना 2019 में भारत और एशिया और अफ्रीका के अन्य विकासशील देशों में पर्यावरण-विकास चुनौतियों के लिए समाधानों की पहचान करने, उन्हें बढ़ावा देने और उन्हें बढ़ाने के लिए की गई थी। हमारा काम स्थिरता और समानता के प्रति प्रतिबद्धता से निर्देशित होता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारे समाधान सामाजिक रूप से न्यायसंगत और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार हैं।

iFOREST का काम उप-राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणीय कार्रवाइयों को गति देने और इसे समर्थन देने के लिए राष्ट्रीय नीतियों और योजनाओं में सुधार करने के लिए क्षेत्रीय प्राथमिकताओं में निहित है। हमारे मूल में, हम एक क्षेत्रीय संगठन हैं जिसका राष्ट्रीय फोकस और अंतर्राष्ट्रीय पहुँच है। हमारा मिशन राष्ट्रीय कार्रवाई को बढ़ाने और वैश्विक प्रभाव बनाने के लिए अपने संसाधनों और विशेषज्ञता का लाभ उठाकर क्षेत्रों की अनूठी जरूरतों को पूरा करना है। हम राष्ट्रीय नीति और योजनाओं को सूचित करने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए अपने क्षेत्रीय ज्ञान का उपयोग करते हैं।

अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, हम स्वतंत्र साक्ष्य-आधारित अनुसंधान करते हैं, नया ज्ञान और नवीन समाधान विकसित करते हैं, जागरूकता बढ़ाने और आम सहमति बनाने के लिए हितधारकों को बुलाते हैं, तथा समाधानों को बढ़ाने के लिए थिंक टैंक, नागरिक समाज, सरकारी एजेंसियों, परोपकारी संस्थाओं और उद्योग के साथ साझेदारी करते हैं।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:

श्रेया मोहन
लीड – पर्यावरण संचार और आउटरीच,
आईफॉरेस्ट
shriya@iForest.global | +91 7042144726